भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3040

27 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात का उत्पादन

3040. डॉ. धर्मस्थल वीरेंद्र हेग्गडे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व स्तर पर इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से दूसरे सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में उभरा है;

(ख) क्या स्पेशियलिटी स्टील के घरेलू उत्पादन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को हाल ही में अनुमोदित किया गया है, यदि हाँ, तो परिव्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्पेशियलिटी स्टील को चुनने के उद्देश्य, मुख्य विशेषताएं और कारण क्या हैं;

(घ) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्या परिणाम निकलने की संभावना है;

(ङ) आज की तारीख के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितनी कंपनियों का चयन किया गया है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत कितना प्रतिबद्ध निवेश, क्षमता अभिवृद्धि और रोजगार सृजित होने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): भारत वर्ष 2018 से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड इस्पात उत्पादक और वर्ष 2019 से तैयार इस्पात का सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में उभरा है।

(ख): सरकार द्वारा दिनांक 22.07.2021 को 6,322 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए एक उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अनुमोदित की गई थी।

(ग): पीएलआई योजना का उद्देश्य इस्पात क्षेत्र में पूँजीगत निवेश आकर्षित करके, रोजगार सृजित करके और प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहित करके देश में 'विशेष इस्पात' के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। योजना की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं - प्रोत्साहनों के 3 स्लैब, भारत में पूँजीकृत

कंपनियों द्वारा ही भागीदारी, योजना के दिशा-निर्देशों में दिए गए निवेश और वृद्धिशील उत्पादन की सीमाओं के लिए प्रतिबद्धता। विशेष इस्पात एक मूल्यवर्धित इस्पात है, जिसमें सामान्य तैयार इस्पात पर कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट और अन्य सभी के माध्यम से संकार्य किया जाता है, जो विशेष गुण वाले अनुप्रयोगों जैसे रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, विशेषीकृत पूँजीगत सामानों आदि में उपयोगी है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए घरेलू इस्पात क्षेत्र के लिए विशेष इस्पात का अतिरिक्त उत्पादन अपेक्षित है।

(घ) से (च): एप्लिकेशन विंडो 15.09.2022 को बंद कर दी गई थी। सरकार को 35 कंपनियों से 79 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 57 आवेदनों को शामिल करते हुए 27 चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। पीएलआई योजना में भागीदारी करने वाली कंपनियों ने 29,530 करोड़ रुपये के निवेश, 24.78 मिलियन टन के डाउनस्ट्रीम क्षमता संवर्धन और लगभग 55,000 रोजगार देने की प्रतिबद्धता की है।

****